आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर जी-20 की मुहर

गरीब व विकासशील देशों को होगा फायदा, गरीब देशों के लोगों को मिलेगी डिजिटल पहचान

राजीव कुमार • नई दिल्ली

वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर भारत के एजेंडा पर जी-20 के सभी देशों ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही गरीब व विकासशील देशों के आर्थिक विकास का रास्ता साफ हो गया। कोरोना महामारी और ठीक उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे विकासशील व गरीब देशों को संकट से उबारने को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने अपना आर्थिक एजेंडा तय किया था। भारत चाहता है कि इन गरीब देशों में भी वित्तीय समावेश हो, सभी लोगों का खाता हो, उन्हें सतत विकास का मौका मिले और उनके यहां भी गरीबी कम हो। इसके लिए भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) के जरिए गरीब व विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने व ग्रीन टेक्नोलाजी पैक्ट का एजेंडा तय किया था, जिस पर दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों ने अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक (एमडीबी) के प्रारूप में बदलाव और उसे और मजबूत बनाने पर भी भारत के एजेंडा पर मुहर लगाई गई। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गरीब व विकासशील देशों को भी उनकी नई जरूरतों के लिए एमडीबी से आसानी से कर्ज मिलेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि अगले दस सालों की जरूरतों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एमडीबी में 200 अरब डालर का एक कोष तैयार किया जाएगा। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस फंड से कर्ज दिए जाएंगे।

जी-20 समिट में एक ग्रुप फोटो खिंचवाने के दौरान (बाएं से) विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लुला डी सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन • पेट

अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रणाली लाने पर भी जी-20 देशों में सहमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने पर भी सभी ने अपनी सहमति दे दी। इस साल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रणाली तैयार करने पर काम शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार, जी-20 के वित्त संबंधी बैठक में भारत, चीन व अमेरिका ही मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रणाली पर बहस करते नजर आए। छोटे-छोटे देशों को तो अभी इस बात का पता ही नहीं है कि उनके देश में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनियां कारोबार कर कमाई कर रही है। । छोटे देशों को इस प्रकार की प्रणाली को अपनाने के लिए टेक्निकल मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने पर भी जी-20 देशों के बीच रजामंदी हुई। इसके तहत एक एक्सचेंज बनाया जाएगा जिसके माध्यम से यह पता चल सकेगा कि किस देश में किसके पास कितने क्रिप्टो है ताकि उनसे टैक्स वसूला जा सके।

आर्थिक विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा (डीपीआइ) के तहत गरीब देशों के लोगों को डिजिटल पहचान दी जाएगी, उनके बैंक खाते खोले जाएंगे और उन्हें यूपीआइ जैसी तेज भुगतान की सुविधा दी जाएगी। कई गरीब देश जो वैश्विक एजेंसियों से लिया कर्ज नहीं चुका पा रहे है, उन्हें भी राहत दी जाएगी। जी-20 देश भविष्य के शहर को तैयार करने के लिए आर्थिक माडल को लेकर भी सहमत हो गए।

भारत शुरू से इस बात पर जोर दे रहा था कि क्रिप्टो को कोई देश अकेला रेगुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह टेक्नोलाजी से जुड़ा मामला है। जी-20 के सभी देश भारत के इस बात से सहमत हो गए हैं और अब वैश्विक स्तर पर इसे रेगुलेट किया जाएगा।जी-20 देशों के नेताओं ने शनिवार को नई दिल्ली घोषणापत्र में जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों में ऋण संबंधी परेशानियों से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने पर सहमति जताई।

स्किल गैप की वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे जी-20 देश

जितेंद्र तर्मा • नई दिल्ली

- **शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जताई प्रतिबद्धता**
- **कुशल कामगारों के प्रवास के उचित प्रबंधन पर जोर, डिजिटल अपस्किलिंग व रीस्किलिंग भी मंत्र**

विश्व के सामने कुशल कामगारों की चुनौती बढ़ती जा रही है। जी-20 देश जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठे तो कौशल विकास भी उनमें अहम था। कई दौर की बैठकों में समूह के प्रतिनिधियों ने अपनी चुनौतियों, अवसरों और अनुभवों को साझा किया। अंततः शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में इसे सहमति के साथ शामिल कर लिया गया है कि स्किल गैप की वैश्विक चुनौतियों से जी-20 के देश मिलकर निपटेंगे। श्रमिकों-कामगारों के हितों को लेकर भी सभी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जी-20 शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने कहा है कि वे स्किल गैप को दूर करने, अच्छे काम को बढ़ावा देने और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुशल श्रमिकों के हितों की चिंता करते हुए सहमति बनी है कि ऐसे कामगारों को एक से दूसरे देश में प्रवासन के लिए उचित प्रबंधन करते हुए अवसर तैयार करने होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी डाटा बनाने के साथ ही नौकरियों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के कवरेज को विस्तार देना होगा। इसके लिए जी-20 नीति के विकास का सभी ने स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास को शामिल कर चुका भारत लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि कौशल

व योग्यताओं का एक अंतरराष्ट्रीय मानक हो और उन्हें पारस्परिक मान्यता दी जाए। जी-20 देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है, जिससे यह राह बनती नजर आ रही है कि प्रवासी कामगारों के सामने योग्यता के भेद का संकट नहीं रहेगा और उनके कौशल को अन्य देशों में भी स्वीकार्यता मिलेगी। स्किलिंग के साथ ही अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोर रहता है। उनके इस मंत्र को भी शिखर सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने माना और खास तौर पर डिजिटल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के कार्यक्रम शुरू करने पर रजामंदी दी है। 'एक देश, एक राशन कार्ड' का सफल प्रयोग कर चुकी मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी पर भी काम शुरू कर दिया है। इस पर विचार के लिए अन्य देशों ने भी सहमति व्यक्त की है।